(ख) यद्यपि नरेला दिल्ली नगर निगम के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में ही है, वहां पर विद्युत का उत्पादन, सम्भरण और वितरण एक प्राईवेट लाइसेंसदार नामतः राष्ट्रीय विद्युत सम्भरण तथा व्यापार निगम (प्राईवेट) लिमिटिड [National Electric Supply and Trading Corporation (Private) Ltd.] का उत्तरदायित्व है। दरों में अन्तर का कारण नरेला में विद्युत उत्पादन और सम्भरण का अधिक लागत ही है।

(ग) इस समय कोई भी तारीख नहीं बताई जा सकती।

नरेला (दिल्ली) की गलियों में बिजली

२४९५. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला के दिल्ली नगर निगम के नागरिक नियंत्रण के अधीन आने के पहले भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेला द्वारा वहां सड़कों पर बिजली का प्रबन्ध था ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम द्वारा सड़कों से बिजली हटा ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सड़कों पर लगी बिजली का साजसामान हटाया नहीं गया, बल्कि मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने ७-९-१९६० से बिजली देना बन्द कर दिया क्योंकि भूतपूर्व अधि-सुचित क्षेत्र समिति नरेला के साथ उनके करार की मियाद इस तारीख को खत्म हो गई। देहली नगर निगम ने मैसर्स नैशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड को बिजली बांटने का जो लाइसेंस दिया था वह मन्सूख कर दिया और हिदायत की कि साजसामान निगम के देहली बिजली प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन कम्पनी ने अदालत से निषेधाज्ञा (इन्जेक्शन) हासिल कर ली जिससे निगम पर यह रोक लग गई कि वह साजसामान न ले। सरकार अभी इस मसले का अन्तिम हल नहीं निकाल पाई है। अभी काम चलाने के लिये, निगम द्वारा मिट्टी के तेल से जलने वाले ८० लालटेन दे दिए गये हैं।

टेलीफोन के कॉल का किराया

२४९६. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) गाजियाबाद से दिल्ली और (२) नरेला से दिल्ली तक प्रत्येक सामान्य टेलीफोन काल का शुल्क क्या है ;

(ख) नरेला के लिये टेलीफोन काल की दरें ऊंची होने के कारण क्या हैं, विशेष रूप से जब कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और नरेला दिल्ली में; और

(ग) इन दरों में समता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (१) स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क १२ न० पै०।

(२) तीन मिनट के सामान्य टेलीफोन काल के लिए ६० न० पै०।

(ख) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को डायल करके स्वयं टैलीफोन मिला सकता है और ऐसी कालों को ट्रंक टेलीफोन प्रचालकों द्वारा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नरेला की दूरी अधिक है और टेलीफोन कालों

को प्रचालकों द्वारा मिलाना पड़ता है । दूरी के आधार पर ६० न० पै० शुल्क लिया जाता है ।

(ग) इस क्षेत्र में टेलीफोन की शुल्क दरों को फिर से निर्धारित किया जा रहा है ।

Sleeping Accommodation in Janata Express

2497. Shri Yajnik: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government generally provided three-tier collapsible berths to give sleeping accommodation to passengers travelling 300 miles or above on all the railways;

(b) whether this facility has been provided in the Janata Express and the other Mails that carry passengers from Ahmedabad or Viramgam to Bombay, which is at a distance of more than 300 miles; and

(c) if not whether Government propose to provide such sleeping facilities to these passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Bogus Railway Tickets

2498. Shri Yajnik: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether bogus railway tickets have been found in large numbers with passengers in the country;

(b) the total number of tickets found during the last year and the total amount of fine collected on that account;

(c) whether some of those tickets were sold by the booking offices of the railways themselves; and

(d) the measures Government have taken to prevent the sale of bogus tickets from the Railway booking offices and elsewhere?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). Only one case of bogus blank paper ticket was detected over the Eastern Railway during the last year. The case is under Police investigation.

(c) No.

(d) Does not arise in respect of booking offices. Frequent announcements are made over the loudspeakers, where provided, requesting passengers not to purchase tickets from any other place except the Railway Booking Counters. Besides, Special Inspectors under the headquarters also move *incognito* and employ sources under them to unearth any illegal activities of undesirable elements.

Irrigation Schemes in Mysore State

2499. Shri S. B. Patil: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any intensive survey has been made regarding the major and medium irrigation projects in Mysore State;

(b) if so, whether a statement together with benefits and approximate estimates of the above-said projects will be laid on the Table; and

(c) the amount spent on such projects in First and Second Five Year Plan periods and provision therefor in the Third Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) and (b). The Central Government does not undertake any surveys of medium and major irrigation schemes unless requested by a State Government. The State Governments themselves undertake surveys and investigations of all major and medium irrigation projects taken up by them for execution.

However, a list of the 1st, the 2nd and the 3rd Plan projects showing their costs, benefits and provision for the 3rd Plan is laid on the Table. [*See* Appendix III, annexure No. 80A].